भारत की अपराध रिपोर्ट और डेटा में नया क्या है

लेखक – दीप्तिमान तिवारी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आतंरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

23 अक्टूबर, 2019

"नवीनतम NCRB रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों, SC/ST अधिनियम के तहत अपमान के मामलों, पुलिस और अदालत द्वारा मामलों के निपटान में देरी की अवधि का परिचय देती है।"

सोमवार को, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने देर हो चुकी 2017 के अपराध डेटा को जारी किया। हालाँकि, यह कुछ महत्त्वपूर्ण डेटा श्रेणियों के बिना था, लेकिन इसमें शामिल डेटा 2016 की अपराध रिपोर्ट की तुलना में अधिक जानकारी के साथ है। इस बार NCRB ने विभिन्न प्रमुखों के तहत तीन दर्जन से अधिक नई श्रेणियाँ और अपराधों की उप-श्रेणियां पेश की हैं।

रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग, खाप हत्याएँ, प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या और धार्मिक कारणों से हत्या के आँकड़ों को छोड़ दिया गया है।

इसके अलावा, 2015 के बाद किसान आत्महत्या के आँकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, हालाँकि, सूत्रों के अनुसार, पूरी तरह से संकलित डेटा 20 महीने पहले ही गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका था।

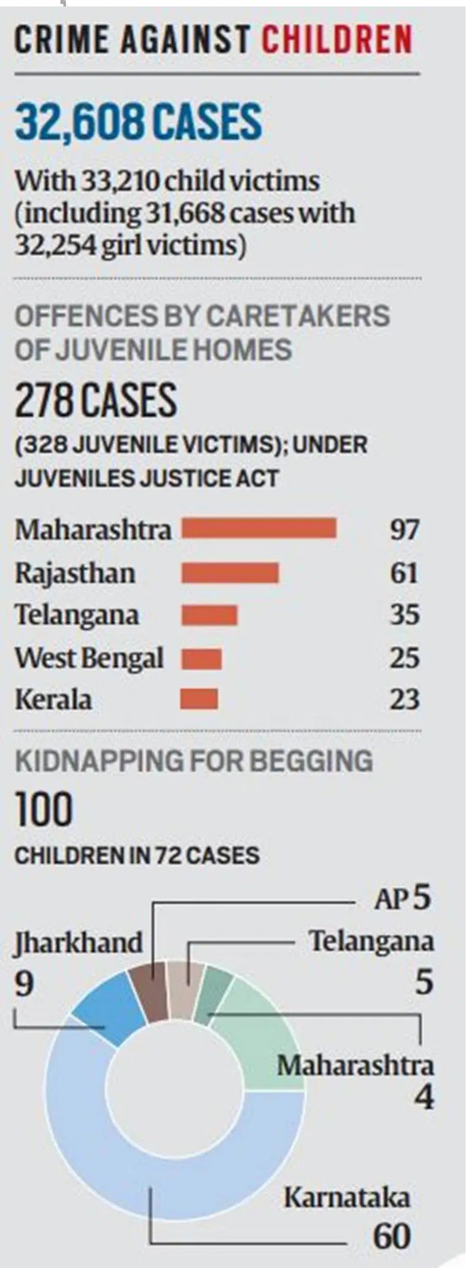

NCRB अपराध रिपोर्ट डेटा: नई श्रेणियाँ

कम से कम चार ऐसी श्रेणियाँ हैं जहाँ डेटा के महत्त्वपूर्ण विविधीकरण को देखा जा सकता है जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अत्याचार, भ्रष्टाचार के मामले तथा पुलिस और अदालतों द्वारा मामलों के निपटान के लिए लिया जाने वाला समय शामिल है। पहली बार, NCRB ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों की श्रेणियों की शुरुआत की है।

दलितों के मामले में एनसीआरबी ने पहली बार अपमान, भूमि हड़पने और सामाजिक बहिष्कार के और अधिक वर्गीकरण के साथ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों पर पहली बार आँकड़ों को प्रकाशित किया है।

NCRB ने लोक सेवकों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के मामले भी दर्ज किए हैं, साथ ही नए प्रमुख अपराध जैसे कि अपहरण, आपराधिक धमकी, साधारण चोट पहुँचाना, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इंटरनेट अपराध और भीख मंगवाने के लिए अपहरण करना शामिल है।

GS World Committed To E

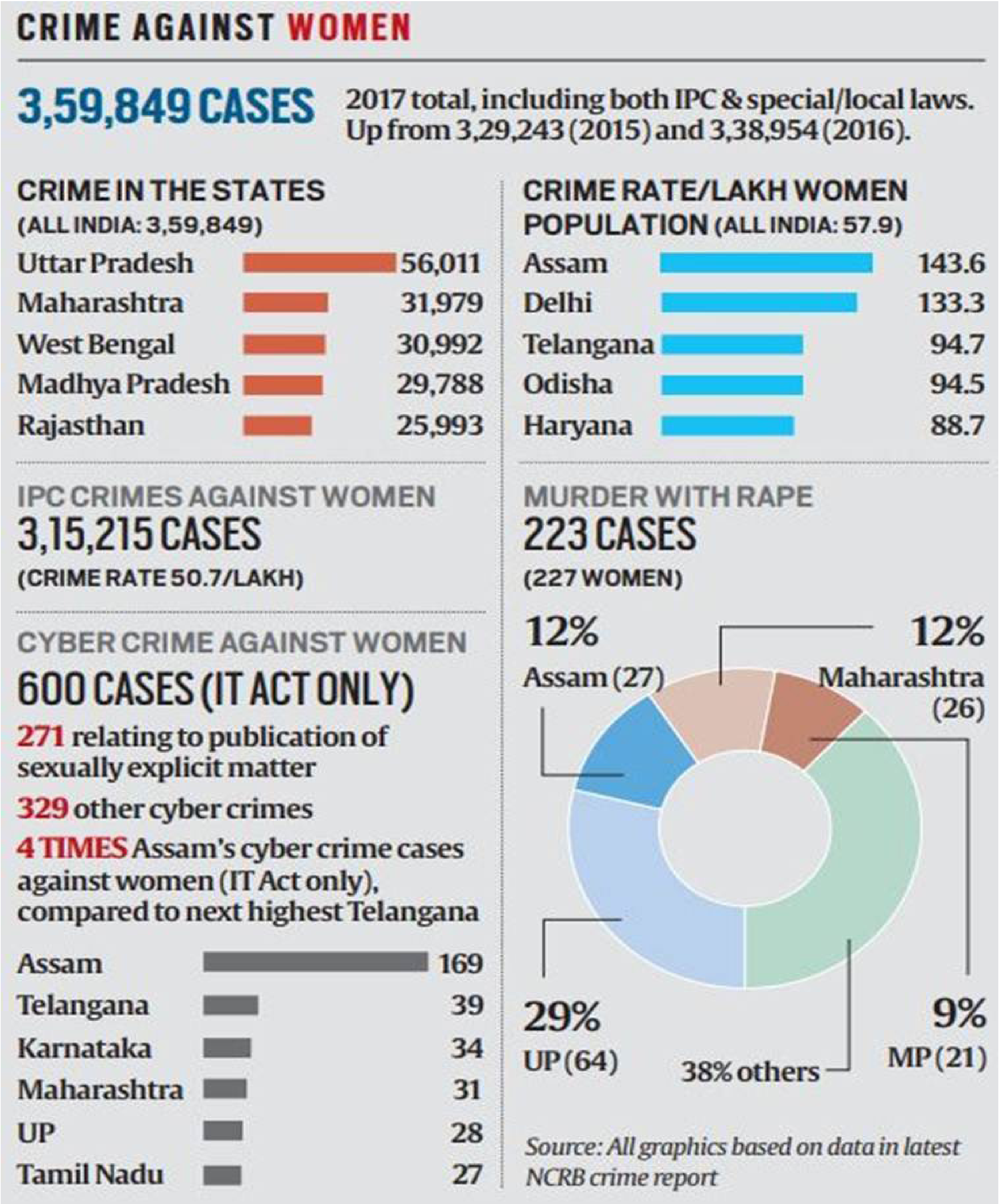

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार एनसीआरबी ने न केवल पुलिस और अदालतों में लंबित मामलों को दर्शाया है बल्कि ये मामले कितने दिनों से लंबित हैं उसे भी दर्शाया है।

महिलाएँ और बच्चे

महिलाओं और बच्चों के मामलों में NCRB ने इस बार 'बलात्कार के साथ हत्या' के भी आँकड़े दर्ज किए हैं। 2017 में देश भर में 33,885 महिलाओं के साथ बलात्कार होने की सूचना मिली थी। इनमें से 227 की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई

थी। आईपीसी और POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अनुसार 28,152 बच्चों के साथ बलात्कार किया गया। इनमें से 151 को बलात्कार के बाद मार दिया गया।

हालाँकि, NCRB ने गैंगरेप की श्रेणी को हटा दिया है जिसे दिसंबर 2012 के गैंगरेप मामले के बाद NCRB डेटाबेस में पेश किया गया था।

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की श्रेणी में एनसीआरबी ने 4,242 अपराधों को दर्ज किया है जिसमें महिलाओं का या तो पीछा किया गया या उन्हें ब्लैकमेल किया गया या उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरों (तस्वीरों के साथ छेड़छाड़) को इंटरनेट पर अपलोड किया गया।

एसएलएल (विशेष और स्थानीय कानून) महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के लिए एक उप-श्रेणी में, महिला-केंद्रित अपराधों की संख्या 600 बताई गई है जिनमें से 271 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत यौन संबंधी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित हैं।

रिपोर्ट में कार्यस्थल पर और सार्वजनिक परिवहन में यौन उत्पीड़न की श्रेणियों को भी पेश किया गया है। 2017 में क्रमशः इन श्रेणियों के तहत 479 और 599 मामले सामने आए हैं।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान 33,606 मामले दर्ज किए गए और 40,420 किशोर पकड़े गए। "आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत कानून के साथ संघर्ष में अधिकांश किशोर 16 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के थे। NCRB ने कहा कि इन मामलों में 40,420 में से 29,194 इसी आयु वर्ग से संबंधित थे, 2017 के दौरान कुल 72.2 प्रतिशत मामले थे।"

न्याय में देरी हुई

NCRB ने हमेशा पुलिस और अदालतों में मामलों की पेंडेंसी पर डेटा एकत्र किया है, यह काफी हद तक ऐसे मामलों की संख्या के बारे में था। नवीनतम रिपोर्ट में, NCRB ने पेंडेंसी की अवधि भी दर्ज की है।

CHARGESHEETS

(21.47 lakh chargesheets in IPC cases, 43% filed beyond 3-month deadline)

Within 1 month	32% (6.88 lakh)
1-3 months	25% (5.37 lakh)
3-6 months	20% (4.35 lakh)
6-12 months	14% (3 lakh)
1-2 years	7.5% (1.58 lakh)
More than 2 years	1.5% (29k)

FAST-TRACK COURTS

(38,004 IPC cases disposed of, 40% took more than 3 years)

Less than 1 month	3% (1,000)
1-3 months	4% (1,540)
3-6 months	8% (3,016)
6-12 months	15% (5,911)
1-3 years	30% (11,401)
3-5 years	19% (7,226)
5-10 years	12% (4,526)
More than 10 years	9% (3,384)

डेटा के अनुसार पुलिस ने 40% मामलों में चार्जशीट में देरी की। आईपीसी अपराधों के लिए, पुलिस को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। लेकिन आँकड़ों से पता चलता है कि कुछ मामलों जैसे दंगा, जिसमें सांप्रदायिक दंगे शामिल हैं, पुलिस ने 60% मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देरी की है। इसमें कहा गया है कि एक वर्ष से अधिक समय तक 3 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, फास्ट-ट्रैक अदालतों के साथ 40% से अधिक मामलों में इन अदालतों को मुकदमे को खत्म करने में तीन साल से अधिक का समय लगा है। वास्तव में, फास्ट-ट्रैक अदालतों में शामिल 3,384 मामलों को 10 से अधिक वर्षों में समाप्त कर दिया गया था।

2017 में फास्ट-ट्रैक अदालतों ने 38,000 विषम मामलों में से, 4,500 से अधिक मामलों को 5-10 वर्षों से चला रहे थे। केवल 11,500 मामलों में एक वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा हुआ था।

कुल मिलाकर, 2,71,779 मामले 2017 के अंत तक लंबित थे।

अन्य आँकड़ा

नए उपश्रेणियों के अंतर्गत दंगे की श्रेणी को भी जोड़ा गया है जिनमें सतर्कता कार्रवाई, पानी, बिजली और संपत्ति पर विवाद और मोर्चा के दौरान दंगे शामिल हैं।

कुछ अन्य नए आँकड़ों में फर्जी खबरें फैलाना शामिल है, जहाँ 257 अपराध दर्ज किए गए हैं। 2017 में चुनाव से संबंधित (952) धर्मो (1,808) और सार्वजनिक स्थानों (29,557) पर अश्लील कृत्यों और गानों से संबंधित अपराधों के अलावा कई अन्य अपराध भी दर्ज किए गए हैं।

GS World टीम...

2017 में साइबर अपराध: NCRB रिपोर्ट

- 2016 की तुलना में 2017 में साइबर अपराधों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार 2017 में लगभग हर पांचवां साइबर अपराध महिलाओं के खिलाफ हुआ है।
- एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में साइबर अपराध के कुल 21,796 उदाहरण दर्ज किए गए, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 77% की वृद्धि हुई है यानी 12, 317। इसके विपरीत, 2016 की संख्या 2015 की संख्या यानी 11,592 से केवल 6% ही अधिक थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में साइबर अपराध की आधी से अधिक घटनाएँ धोखाधड़ी से संबंधित थीं। '2017 के दौरान, 56 प्रतिशत साइबर अपराध के 21,796 मामलों में से 12,213 मामले धोखाधड़ी के मकसद से किये गये थे, इसके बाद 6.7 प्रतिशत (1,460 मामले) यौन शोषण और 4.6 प्रतिशत (1,002 मामले) बदनाम करने के लिए किये गये प्रयास से संबंधित था।'
- देश के खिलाफ घृणा भड़काने के लिए साइबर अपराध के 206 मामले दर्ज किए गए और इसमें से 139 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध थे। 110 साइबर अपराध आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित थे।

	WOMEN	CHILDREN
Cyber Blackmailing/Threatening	132	1
Cyber Pornography/Hosting/Publishing Obscene Sexual Materials	271	7
Cyber Stalking/Cyber Bullying of Women	555	7
Defamation/Morphing	50	NA
Fake Profile	147	3
Other Crimes	3,087	70
TOTAL	4,242	88

- रिपोर्ट के अनुसार, देशव्यापी, साइबर अपराध की दर - अर्थात, प्रति 100,000 जनसंख्या पर साइबर अपराधों की संख्या - 2017 में 1.7 थी।

राज्यों की स्थिति

- कर्नाटक में 2017 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर सबसे अधिक साइबर अपराध 5 की दर से किए गए। प्रति 1,00,000 की आबादी पर 3.3 की दर से साइबर अपराध तेलंगाना में देखे गये, इसके बाद महाराष्ट्र 3 की दर से और उत्तर प्रदेश 2.2 दर से हैं।
- पूर्ण संख्या में, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, यूपी ने साइबर अपराधों की सबसे बड़ी संख्या (4,971) दर्ज की, इसके बाद महाराष्ट्र (3,604), और कर्नाटक (3,174) का स्थान हैं। केंद्र

शासित प्रदेशों में, 2017 में सबसे अधिक साइबर अपराध दिल्ली (162) में दर्ज किए गए थे।

महिलाओं और बच्चों की स्थिति

- 2017 में देश में दर्ज 21,796 साइबर अपराधों में से, 4,242 – लगभग 19.5% महिलाओं के खिलाफ, और 88 बच्चों के खिलाफ हुए थे।
- महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध साइबर ब्लैकमेल, साइबर पोर्नोग्राफी या अश्लील यौन संबंधी सामग्री के प्रकाशन, साइबर पीछा या मानहानि या छेड़छाड़ और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी आदि से संबंधित थे।
- बच्चों के खिलाफ अपराधों में ऑनलाइन गेम आदि के माध्यम से किए गए इंटरनेट अपराध शामिल हैं, यह पहली बार है कि NCRB ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों की प्रकृति पर डेटा संकलित किया है।
- 2017 में, साइबर अपराध के मामलों में कुल 11,601 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 8,306 पर आरोप आरोपित किए गए थे, लेकिन केवल 162 को दोषी ठहराया गया था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 2017 के अपराधों का डेटा प्रकाशित किया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. पहली बार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों की श्रेणियों की शुरूआत की है।
2. इस डेटा में लोक सेवकों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के मामले भी दर्ज किए गए हैं।
3. यह डेटा अधिकांशत: पुलिस और अदालतों में लंबित पड़े मामलों पर एकत्र किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Recently, National Crime Records Bureau (NCRB) has published the data of crimes of 2017, with reference to this, consider the following statements: -

1. For the first time, NCRB has introduced the categories of cyber crimes against women and children.
2. It has also recorded disproportionate assets cases against public servants in the data.
3. This data collected is based on cases mostly pending in Police stations and courts.

Which of the above statement is/are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3
(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारत में महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति में आया बदलाव तथा न्याय में देरी गंभीर चिंता का विषय है।' हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

'The change in the trend of crimes against women in India and delay in justice is a matter of grave concern.' Analyze this statement in the context of the recently released National Crime Records Bureau (NCRB) report.

(250 words)

नोट : 22 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।